

म्यांमार में तख्ता पलट का एक वर्ष : एक विश्लेषण



डॉ. अखय राज मीणा

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिकन्दरा, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत ने सन् 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अपनी 'पूर्व की ओर देखो' नीति की घोषणा की, जिसका ध्येय आसियान देशों का दिल जीतना था। इसी नीति को 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार की नयी राजधानी 'नाय-पी-ता' में आसियान सम्मेलन में 'पूर्व के लिए करो' के नये नाम से लांच किया। म्यांमार आसियान का सदस्य है, जो भारत की 'पूर्व के लिए करो' नीति (एक्ट ईस्ट पॉलिसी) का केन्द्रीय स्थल है। दशकों तक सैन्य तानाशाही के साये में रहे म्यांमार को कुछ साल पहले ही लोकतांत्रिक बयार की सौगात मिली थी, मगर अफसोस कि यह सिलसिला ज्यादा लम्बा नहीं चल सका। फलते-फूलते लोकतंत्र पर म्यांमार में बीते दिनों ग्रहण लग गया और सेना ने फिर से देश की कमान सम्भाल ली। म्यांमार में एक फरवरी, 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसका भारत की विदेश नीति तथा वैश्विक राजनीति पर गहरा और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ना अवश्ययंभावी है। फरवरी, 2022 में इस घटनाक्रम को एक वर्ष हो गया है, ऐसे में इसके कारणों, प्रभावों तथा वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। प्रस्तुत आलेख में म्यांमार में आंतरिक स्थिति, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तथा भारतीय विदेश नीति में वर्तमान म्यांमार आदि के विषय में जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत आलेख में पुस्तकालयी, ऐतिहासिक तथा अन्य समीचीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है और उनके माध्यम से म्यांमार की स्थिति अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य एवं भारत म्यांमार सम्बन्धों के बदलते परिदृश्य को समझने का प्रयास किया है।

संकेताक्षर—तख्ता पलट, चीनी फैक्टर, ट्रेक-टू डिप्लोमैसी

प्रस्तावना

म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जो 1885 से 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा है। भारत की 1643 किमी. लम्बी सीमा म्यांमार से लगती है।¹ दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में 725 किमी. लम्बी तट रेखा भी है।² म्यांमार, भारत के लिए न केवल भू-राजनीतिक, वरन् एक संक्रमणकालीन देश के रूप में भी महत्वपूर्ण है।³ म्यांमार रणनीतिक रूप से पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया के त्रि-संगम (ट्राई-जंक्शन) पर अवस्थित है।⁴ 'पूर्व की ओर देखो' नीति (लुक ईस्ट पॉलिसी) की शुरुआत तक भारत ने म्यांमार में लोकतांत्रिक आन्दोलन का समर्थन किया तथा उसकी हमेशा यह आकांक्षा रही कि म्यांमार में

लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। भारत की यह आकांक्षा 2008 के संविधान के तहत चरणबद्ध तरीके से 2015 के चुनाव में पूर्ण होने की सम्भावना बनी, जब सू की, की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को इन चुनावों में बहुमत मिला और 2020 के आम चुनावों में एनएलडी को पुनः बहुमत मिला। 1 फरवरी, 2021 को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने एनएलडी सरकार का तख्ता पलट कर दिया।⁵

आंग सान सूहे के नेतृत्व में एनएलडी सरकार को 1 फरवरी, 2021 से ही दूसरा कार्यकाल प्रारम्भ करना था। सेना के स्वामित्व वाले 'मयावाड़ी टीवी' ने तख्ता पलट की घोषणा की और बताया कि सेना प्रमुख (कमांडर इन चीफ) जनरल

मिन आंग लाइंग ने एक साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।⁶

सेना ने वर्ष 2008 के संविधान के अनुच्छेद 417 का हवाला दिया, जो आपातकाल में सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है।⁷

सेना ने उपराष्ट्रपति मिंट स्वे को एक वर्ष के लिए सरकार का प्रमुख बनाया है, जो पहले सैन्य अधिकारी रह चुके हैं।⁸ सेना ने देश में शासन संचालन के लिए एक 11 सदस्यीय समिति बनाई है।

म्यांमार में तख्ता पलट क्यों हुआ ?

एक वर्ष पूर्व म्यांमार में हुआ तख्ता पलट महज एक संयोग मात्र नहीं था। इसके पीछे म्यांमार की सांस्कृतिक-राजनीतिक परिस्थितियों, घटनाओं एवं इतिहास से जुड़े अनेक कारण थे। म्यांमार में तख्ता पलट के प्रमुख कारण निम्नांकित थे—

1. सेना और आंग सान सू की के बीच मतभेद—म्यांमार का वर्तमान संविधान वर्ष 2008 में सेना ने ही तैयार किया था। इस संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर सेना के नियंत्रण को सुनिश्चित करते हैं। इस संविधान के तहत संसद में सेना के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व रहती हैं।⁹

म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। 2008 के संविधान के तहत सुरक्षा से जुड़े सभी मन्त्रालयों पर सेना का नियंत्रण है।¹⁰

म्यांमार में गृह, रक्षा और विदेश नीति (सीमायी मामलों समेत) मन्त्रालय सेना के पास हैं। 2008 के संविधान में एक प्रावधान यह भी है कि जिस नागरिक का पति, पत्नी या बच्चे विदेशी नागरिक हैं, वह देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति पद) पर नहीं बैठ सकता। आंग सान सू की के दिवंगत पति (माइकल एरिस) तथा दोनों बच्चे (एलेक्जेंडर व किम) ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए वे 2015 में प्रचण्ड बहुमत के बावजूद देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकीं। वे 'स्टेट काउंसलर' के पद के साथ वास्तविक राष्ट्रीय नेता बन गईं (भारत के प्रधानमंत्री की भांति)। म्यांमार में सेना को संविधान में किसी बदलाव पर वीटो लगाने का भी अधिकार है।¹¹

आंग सान सू की सरकार ने विवादित दस्तावेज में बदलाव का वादा किया था। इसी क्रम में एक समिति बनाने के प्रस्ताव पर संसद में मतदान कराया गया, जो भारी मतों से पारित हो गया था। इसके बाद सेना को यह भय सताने लगा कि सत्ता से उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। ऐसे में सेना में सू की, की इस कवायद को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया।¹²

2. रोहिंग्या मुस्लिम—2017 में म्यांमार की सेना ने अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों पर भारी मात्रा में आक्रमण किये, जिससे बड़ी संख्या में रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गये। इस मुद्दे पर सू की ने न केवल सेना को मौन समर्थन दिया, वरन् अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सेना का बचाव भी किया। इसके दो तरह के परिणाम सू की के लिए सामने आए—पहला देश में सू की के लिए स्वीकार्यता बढ़ गई, विशेषतः बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय में, दूसरा—अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सू का समर्थन कम हो गया।

3. चीनी फैक्टर—चीन और म्यांमार की सेनाओं के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। चीन ने म्यांमार को 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति के तहत तरजीह दी है।¹³

यानी भारत को घेरने तथा म्यांमार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चीन ने म्यांमार में तख्ता पलट करवाया है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर चीन ने जिस प्रकार ठण्डी प्रतिक्रिया दी तथा इस मुद्दे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आपात बैठक में चीन ने जिस प्रकार म्यांमार का बचाव किया, उससे इस तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ नजर आता है।

4. आम चुनाव के परिणाम—8 नवम्बर, 2020 को म्यांमार में संसदीय चुनाव हुए। इन चुनावों में आंग सान सू की, की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने 498 में से 396 सीटों पर जीत दर्ज की है।¹⁴ एनएलडी ने 83 प्रतिशत सीटें जीतीं। इस चुनाव में एनएलडी का मुख्य मुकाबला यूनियन सॉलिडरिटी एण्ड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) से हुआ था। यूएसडीपी को सेना का राजनीतिक संगठन माना जाता है।¹⁵

अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें हाथ में रहने के बावजूद सेना द्वारा नियंत्रित यह पार्टी 2020 के चुनाव में सत्ता में आने लायक सीटें हासिल नहीं कर पायी, तो यूएसडीपी तथा सेना

ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया। जैसे-जैसे एनएलडी के दोबारा सरकार बनाने की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे-वैसे सेना में तिलमिलाहट भी बढ़ती जा रही थी। चुनाव परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी। देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमीशन ने जनवरी, 2021 के अन्त में सेना (तथा यूएसडीपी) के आरोपों को खारिज कर दिया।¹⁶ यूईसी ने नयी सरकार के गठन को सुनिश्चित करने के लिए 1 फरवरी, 2021 से संसद का सत्र बुलाना तय किया था।

नवनिर्वाचित संसद को 1 फरवरी, 2021 से कार्य प्रारम्भ करना था और इसी दिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया।¹⁷ सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है।¹⁸

5. कमांडर इन चीफ की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की चाह—म्यांमार में मार्च, 2011 से जनरल मिन आंग लाइंग (Min Aung Hlaing) कमांडर-इन चीफ हैं। वे जुलाई, 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, किन्तु वे देश का राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा पाले हुए थे। ऐसा सैन्य शासन के बिना असम्भव था, इसलिए उन्होंने देश को सेना के हवाले किया। इससे उनका कार्यकाल एक वर्ष तो बढ़ ही गया और वे एक वर्ष बाद भी सत्ता में हैं।

मिन आंग लाइंग (64 वर्षीय)

- यंगून विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की।
- 1974 में डिफेंस सेवा अकादमी में प्रवेश लिया।
- अगस्त, 2010 में जॉइन्ट चीफ ऑफ स्टाफ बने।
- मार्च, 2011 में कमांडर इन चीफ बने।

6. बौद्ध धर्म और राजनीति—म्यांमार की सेना बौद्ध भिक्षुओं को देश की राजनीति में प्रभाव को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाती है, वहीं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने राजनीति की धर्म से दूरी के लिए कुछ कदम उठाए हैं जो सेना और बौद्धों को रास नहीं आए।¹⁹ उदाहरण के लिए, जून, 2019 में देश के धार्मिक मामलों और संस्कृति मन्त्रालय ने एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी कर कहा था कि यदि कोई बौद्ध भिक्षु किसी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होता है और उसके जरिए समुदाय को अस्थिर करने में भड़काऊ कार्य करता है तो

उसे पुरोहित पद से हटा दिया जाएगा या वह उस पद का हकदार नहीं होगा।²⁰

दूसरा, मई, 2019 में एनएलडी की सरकार ने बौद्धों के लिए राष्ट्रवादी आन्दोलन चलाने वाले यू विराथु के खिलाफ म्यांमारी दण्ड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया।²¹ यू विराथु ने 2014 में म्यांमार की सेना के समर्थन से एमवीटी नामक एक शक्तिशाली संगठन खड़ा किया था, जो चुनावों में एनएलडी के खिलाफ कार्य करता है।²²

सू ची के समर्थकों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का ऐलान किया।²³ सू ची की पार्टी के निर्वाचित विधायकों ने 5 फरवरी, 2020 को एक ऑनलाइन बैठक करके स्वयं को लोगों का वास्तविक वैधानिक प्रतिनिधि घोषित किया तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को देश की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करने की अपील की।²⁴ म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक गुटों ने 'नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट' (एनयूजी) बनाई।²⁵ साथ ही नागरिकों के हथियारबन्द संगठनों, जिन्हें 'पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज' कहा जा रहा है, ने बड़ी तेजी से खुद को हथियारों से लैस किया है और अब वे लगातार सैन्य बलों के साथ संघर्ष कर रहे हैं।²⁶

मानवाधिकार संगठन 'असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स (आप) की ओर से बीबीसी हिन्दी को दी गई जानकारी के मुताबिक म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शनों पर आठ सितम्बर, 2021 तक हुई सैन्य कार्रवाईयों में 1318 आम लोगों की मौत हुई है।²⁷

म्यांमार में तख्ता पलट पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने म्यांमार की सेना से आंग सान सू की तथा दूसरे नेताओं की रिहाई तथा लोकतंत्र की पुनर्बहाली की मांग की।²⁸

जी-7 देशों ने म्यांमार की सेना से तुरन्त आपातकाल खत्म करने और निर्वाचित सरकार को बहाल करने की अपील की।²⁹

1 फरवरी, 2021 को सेना ने स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की के साथ राष्ट्रपति विन म्याँत को भी हिरासत में ले लिया।³⁰ ऐसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सेना से लोकतांत्रिक सुधारों के प्रति गम्भीरता दिखाने को कहा।³¹

26 अक्टूबर, 2021 को आसियान देशों का तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन (दारुस्लाम बूनेई) शुरू हुआ था। इसमें म्यांमार का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।³²

दरअसल, आसियान ने सैनिक तख्ता पलट (मिलिटरी कॉप) की अगुवाई करने वाले जुंटा नेता मिन आंग लाइंग को सम्मेलन में शिरकत करने की इजाजत नहीं देने का अनोखा फैसला लिया था।³³

म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और भारत

म्यांमार में 1 फरवरी, 2021 को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार को हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार सेना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया।³⁴ संयुक्त राष्ट्र ने चुनी हुई नेता आंग सान सू की समेत लोकतांत्रिक नेताओं की रिहाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग भी की है।³⁵

संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में 119 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सिर्फ बेलारूस ने इसके खिलाफ वोट किया। भारत, रूस और चीन समेत 36 देश इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे।³⁶

रूस और चीन म्यांमार की सेना के सबसे बड़े हथियार सप्लायर हैं।³⁷ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून, 2021 में पारित अपने प्रस्ताव में म्यांमार के सैनिक शासन को हथियारों की मदद रोकने का आह्वान किया था, लेकिन चीन ने उसका ख्याल नहीं रखा।³⁸ दिसम्बर, 2021 में उसने म्यांमार को मिंग क्लास पनडुबी सौंपी, जिसका अब म्यांमार की नौसेना इस्तेमाल कर रही है।³⁹

भारतीय रुख

भारत के लिए म्यांमार रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के आदर्श के लिए भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से आँख मूंदकर नहीं बैठ सकते। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों और चीन की कुटिल चालों के मद्देनजर तो ऐसा बिलकुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने तख्ता पलट के बाद म्यांमार के घटनाक्रम पर बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार के मुद्दे पर हुए मतदान में भी भारत अनुपस्थित

रहा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी दिसम्बर, 2021 में दो दिवसीय म्यांमार यात्रा पर गए।⁴⁰ वहाँ उन्होंने पड़ोसी देश (म्यांमार) में जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाली पर जोर दिया।⁴¹ म्यांमार की सेना द्वारा आंग सान सू की की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार को गत एक फरवरी को अपदस्थ किये जाने के बाद यह भारत की तरफ से उस देश से किया गया पहला उच्च स्तरीय संपर्क है।⁴² अप्रैल, 2021 में जकार्ता में आसियान नेताओं की बैठक में पाँच बिन्दुओं का एक समझौता किया गया, जो इस प्रकार है⁴³—(i) हिंसा को समाप्त करना, (ii) सभी पक्षों के बीच एक रचनात्मक संवाद, (iii) वार्ता की सुविधा के लिए एक विशेष आसियान दूत का चयन, (iv) सहायता की स्वीकृति और (v) इस दूत द्वारा म्यांमार की यात्रा। भारत ने आसियान की इस पहल का स्वागत एवं समर्थन किया है।⁴⁴

एक प्रमुख विदेश नीति संवाददाता इन्द्राणी बागची के शब्दों में म्यांमार के सन्दर्भ में भारत 'दोहरे-ट्रैक' वाला दृष्टिकोण अपना रहा है।⁴⁵ एक तरफ वह अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ वह म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की वकालत कर रहा है। यही कारण है कि उसने सैन्य जुन्टा के साथ सम्बन्ध बनाए रखने वाला कदम उठाया है।

निष्कर्ष

म्यांमार में तख्ता पलट के एक वर्ष के बाद भी सैन्य शासन ने लोकतंत्र बहाली का कोई संकेत नहीं दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश प्रतिबंधों का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जो म्यांमार के सैन्य शासकों को चीन की गोद में बैठने का कार्य करेगा। भू-रणनीतिक, सुरक्षा तथा सामरिक हितों को देखते हुए भारत ने म्यांमार के साथ सम्बन्ध बनाए रखने का कदम उठाकर सही कदम उठाया है। आसियान पहल के साथ संवाद का रास्ता ही म्यांमार के साथ सही डीलिंग हो सकती है। 1992 में भारत ने म्यांमार के सैनिक शासकों के साथ 'रचनात्मक संलग्नता' की जो नीति अपनाना प्रारम्भ की उसे अब भी भारत को जारी रखना चाहिए।⁴⁶ म्यांमार के साथ व्यापारिक एवं परियोजना सम्पर्क जारी रखते हुए वहाँ लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय प्रयास जारी रहने चाहिए। भारत को अप्रवासी भारतीयों की म्यांमार की नागरिकता दिलाने के मामले में भी सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, भूपेन्द्र, चीन के चंगुल में न फँसने पाए म्यांमार, अमेरिका को अपनाती होगी दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति, जागरण, 11 फरवरी 2021, एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जागरण डॉट कॉम/एडिटरियल
2. उपर्युक्त
3. दहिया, रुमेल एण्ड बेहुरिया, अशोक के., इण्डियाज नेबरहुड चैलेन्जेज इन द नक्स्ट टू डिसेड्स, पेन्टागन प्रेस न्यू देलही, फर्स्ट पब्लिशड इन 2012, पृ.सं. 110
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 10
5. नवभारत टाइम्स, 02 फरवरी, 2021 नवभारतटाइम्स डॉट कॉम
6. नवभारत टाइम्स, 01 फरवरी, 2021 नवभारतटाइम्स डॉट कॉम
7. उपर्युक्त
8. उपर्युक्त
9. विद्रोही, विजय, भारत के लिए म्यांमार क्यों जरूरी है, एबीपी न्यूज, 07 फरवरी, 2021 एबीपीलाइव डॉट कॉम
10. मिश्रा, रमेश, जागरण, (बीजिंग, ऑनलाइन डेस्क), 02 फरवरी, 2021, एम डॉट जागरण डॉट कॉम
11. उपर्युक्त
12. उपर्युक्त
13. न्यूज 18 हिन्दी, 03 फरवरी, 2021, हिन्दी डॉट न्यूज 18 डॉट कॉम
14. अमर उजाला, यंगून, 31 जनवरी, 2021, अमरउजाला डॉट कॉम तथा जीन्यूज, 03 फरवरी, 2021, जीन्यूज डॉट इण्डिया डॉट कॉम
15. उपर्युक्त
16. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021, एम डॉट लाइवहिन्दुस्तान डॉट कॉम
17. नवभारत टाइम्स, 01 फरवरी, 2021 नवभारतटाइम्स डॉट कॉम
18. आज तक, नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021, आज तक डॉट कॉम
19. तनिष्क, म्यांमार मं तख्ता पलट से प्रभावित होंगे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश, संवेदनशीलता से निपटने की जरूरत, जागरण, 05 फरवरी, 2021, एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जागरण डॉट कॉम/एडिटरियल
20. उपर्युक्त
21. उपर्युक्त
22. उपर्युक्त
23. म्यांमार में तख्ता पलट: आंग सान सू की पर कई आरोप, 15 फरवरी तक हिरासत में, बीबीसी न्यूज, 03 फरवरी, 2021 एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम
24. फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 08 फरवरी, 2021, फाइनेंसियल एक्सप्रेस डॉट कॉम
25. दीक्षित अभिषेक, म्यांमार इश्यू: चीन की मदद की वजह से बेपरवाह बने म्यांमार के सैनिक शासक, अमर उजाला, यंगून, 18 फरवरी, 2022, एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अमरउजाला डॉट कॉम
26. मट्टो, शशांक, म्यांमार में तख्ता पलट का एक साल: 'म्यांमार नीति' को लेकर उलझन में भारत, ओआरएफ, 10 फरवरी, 2022 एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ओआरएफऑनलाइन डॉट ओआरजी
27. ओवन, लारा तथा अंग कू कू, म्यांमार: उत्पीड़न झेलने वाली महिलाओं ने बताया नजरबन्दी शिविरों में क्या हो रहा है, बीबीसी न्यूज, 13 दिसम्बर, 2021 एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम
28. इकोनॉमिक टाइम्स, 05 फरवरी, 2021 एम डॉट इकोनॉमिकटाइम्स डॉट कॉम
29. म्यांमार में तख्ता पलट: आंग सान सू चीप र कई आरोप, 15 फरवरी तक हिरासत में, बीबीसी न्यूज, 03 फरवरी, 2021 एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम
30. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021 एम डॉट लाइवहिन्दुस्तान डॉट कॉम
31. बीबीसी न्यूज, 01 फरवरी, 2021, एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम
32. बनर्जी, श्रीपर्णा एवं तारुषि सिंह, म्यांमार: फौजी तख्ता पलट के बाद म्यांमार में कैसे तेजी से बढ़ रहा है। चीन का निवेश, ओआरएफ, 27 नवम्बर, 2021, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ओआरएफऑनलाइन डॉट ओआरजी
33. उपर्युक्त

-
34. बीबीसी न्यूज़, म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ यूएन की पहल, भारत रहा दूर, 19 जून, 2021 एचटीटीपीएस:// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम
 35. उपर्युक्त
 36. उपर्युक्त
 37. उपर्युक्त
 38. दीक्षित, अभिषेक, पूर्वोक्त
 39. उपर्युक्त
 40. तिवारी, अजीत, तख्ता पलट के बाद पहली बार म्यांमार पहुँचे विदेश सचिव, सैन्य शासन को चीन के समर्थन के चलते दुविधा में भारत, 22 दिसम्बर, 2021, टीवी 9 हिन्दी डॉट कॉम
 41. अनवर, म्यांमार में जल्द से जल्द बहाल हो लोकतंत्र, बोले विदेश सचिव, श्रृंगला, सीमा पर हिंसा रोकने और शांति कायम करने पर भी दिया जोर, टीवी9 हिन्दी, 23 दिसम्बर, 2021, टीवी 9 हिन्दी डॉट कॉम
 42. उपर्युक्त
 43. राजगोपालन, राजेश्वरी पिल्लई, म्यांमार : तख्ता पलट के बाद भारतीय विदेश सचिव की दो दिवसीय कूटनीतिक यात्रा, ओआरएफ, 7 जनवरी, 2022, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ओआरएफऑनलाइन डॉट कॉम
 44. उपर्युक्त
 45. उपर्युक्त
 46. चक्रवर्ती, प्रो. त्रिदिब, भारत-म्यांमार: बदलते प्रतिमान और रचनात्मक संलग्नता, वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली, नवम्बर-दिसम्बर 2011 (3-4), पृ.सं. 29